राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 05 जुलाई 2026

वर्ष 14, अंक 87, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

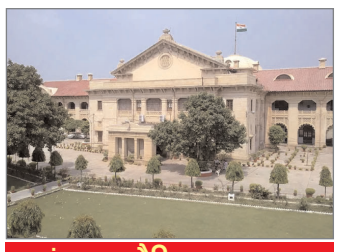

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

महाकुंभ-2025 को नवाचार हेतु मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार...03

एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों का खेल उजागर...04

गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के कथित मॉड्यूल का किया भंडाफोड़

● मदरसा नेटवर्क से कैसे गुजरात को आतंकी टारगेट पर ले रहा था पाकिस्तान, क्या था 'दावत' वाला प्लान

● गुजरात व मध्य प्रदेश से 8 संदिग्ध गिरफ्तार, मदरसों के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप

अहमदाबाद। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई के दौरान आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग संगठन के स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे थे और राज्य में आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास में जुटे थे।

एटीएस के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू हुई जांच के दौरान हुआ। बताया गया कि डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तकनीकी और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई, जिसके आधार पर गुजरात के बनासकांठा, नवसारी और पाटन जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के देवास में संयुक्त छापेमारी की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि संदिग्धों ने 'दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद' नाम से एक स्थानीय मॉड्यूल तैयार किया था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से नए लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता था और संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। एटीएस के अनुसार, इस मॉड्यूल को लगभग तीन लाख रुपये की फंडिंग भी प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक पुरानी कार खरीदकर उसका स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित नहीं कराया था, ताकि उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का संदेह न हो। एजेंसी का कहना है कि इस वाहन का उपयोग कथित तौर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन में किया जाता था।

एटीएस का आरोप है कि कुछ स्थानीय मदरसों में 'दावत' नाम से अभियान चलाकर नए लोगों तक पहुंचने और उन्हें संगठन की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही होगा।

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को सिद्धपुर स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा तथा एक अन्य संदिग्ध को जामिया रहमानिया मदरसा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में अहमद अब्दुल्लाह गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुर्ग, मोहम्मद आमिर घाघा और मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा सहित कुल आठ लोग शामिल हैं। एटीएस के अनुसार, तलाशी के दौरान 254 पृष्ठों का कथित प्रचार सामग्री, पाकिस्तान में प्रकाशित कुछ पुस्तकें तथा आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर को संबोधित बताए जा रहे कुछ पत्र भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामग्री की फोरेंसिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है। जांच एजेंसी ने कहा है कि पूरे नेटवर्क के अन्य संभावित संपर्कों और वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

गुजरात एटीएस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), धारा 17 (आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (आतंकी साजिश), धारा 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता) और धारा 39 .(आतंकी संगठन को समर्थन देना) शामिल हैं. इसके अलावा आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 148 और धारा 61 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, ये धाराएं गंभीर आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ अपराध करने की योजना से जुड़ी हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन आरोपियों के के तार देश और विदेश में किन-किन लोगों से जुड़े हुए थे एटीएस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे थे सुरक्षा एजेंसियां उनके डिजिटल उपकरणों, वित्तीय लेनदेन और संपर्कों की जांच कर रही हैं. इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां या बड़े खुलासे होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

तीन तलाक-हलाला पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

● हलाला के नाम पर नाबालिग से यौन शोषण मामले में समझौता रद्द करने से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला के नाम पर नाबालिग से कथित यौन शोषण और बाद में गैंगरेप के आरोपों से जुड़े गंभीर मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक प्रथाओं या व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में किसी भी आपराधिक कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में विस्तृत आपराधिक जांच आवश्यक है और प्रारंभिक स्तर पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने CRLP(A) 8465/2026 सहित चार संबंधित आपराधिक रिट याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने पहले दी गई अंतरिम राहतों को भी समाप्त कर दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति कानूनन मान्य नहीं होती। यदि किसी नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाए गए हैं तो वह स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी धार्मिक परंपरा या प्रथा के नाम पर किए गए अपराधों को कानून की नजर में उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के आरोप संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं तथा अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता का निकाह वर्ष 2015 में मात्र 15 वर्ष की आयु में कराया गया था। वर्ष 2016 में पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने के बाद दोबारा विवाह का झांसा देकर कथित तौर पर उसे जबरन निकाह हलाला के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में उसका पुनः निकाह हुआ।

आरोप है कि वर्ष 2021 में पति ने दूसरी शादी करने के बाद पीड़िता को तलाक दे दिया। बाद में संतान न होने पर तीसरी बार विवाह का झांसा देकर उसे धमकाया गया और 19 फरवरी 2025 को हलाला के नाम पर अपने दो भाइयों के माध्यम से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया गया। इस मामले में कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष और विस्तृत आपराधिक जांच आवश्यक है तथा इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

संक्षिप्त ख़बरें

बिहरोजपुर गंगा घाट पर अवैध बालू खनन का भंडाफोड़, सात पर मुकदमा

गोपीगंज। बिहरोजपुर गंगा घाट पर अवैध बालू खनन व परिवहन के मामले में गोपीगंज पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान बालू लदे दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़े गए, जबकि एक चालक मौके से फरार हो गया। खान निरीक्षक की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में जय देवी, राजन कुमार, गोलू, राकेश, अरविंद कुमार, शशिकांत तथा धीरज निशाद को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

हैंडपंप पर पानी भरते समय सर्प ने महिला को काटा

कोंच (जालौन)- घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भर रही एक बुजुर्ग महिला को सर्प ने काट लिया। उपचार के लिए महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला जवाहर नगर कोंच निवासी जुवैदा (64) पत्नी इस्माइल शुक्रवार की दोपहर अपने घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भर रही थी। इसी दौरान अचानक वहां निकले एक सर्प ने उसके हांथ में काट लिया। सांप के काटते ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने समय गंवाए बगैर तत्काल ही जुवैदा को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। फिलहाल महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है।

जेवर नगदी सहित नाबालिग किशोरी को ले भागे दो युवक

कोंच(जालौन)- नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने पर पिता ने पुलिस से कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। कस्बा कोंच निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीती 2 जुलाई को उसकी नाबालिग बेटी को एक गांव निवासी दो युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गए। बेटी घर में रखे सोने चांदी के तमाम जेवर और करीब 62 हजार रुपए नगदी सहित जरूरी कागजात भी उठाकर साथ ले गई है। उक्त दोनों युवकों के परिजनों को बताया तो परिजन गाली गलौच करने पर आमादा हैं। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने सभी जगह बेटी की तलाश ली लेकिन उसका अब तक कहीं कोई पता नहीं चल सका है। अनहोनी की आशंका जताते हुए उसने पुलिस से कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है।

सूचना निदेशक विशाल सिंह ने पत्रकारों के हित में उठाया अहम कदम

● आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान, पत्रकारों के लिए जल्द शुरू होगा विशेष ऑनलाइन पोर्टल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा शीघ्र ही उनके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित होता है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

सूचना निदेशक ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना विभाग शीघ्र ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल के प्रारंभ होने की सूचना सभी संबंधित पत्रकारों को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पहल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने सूचना निदेशक विशाल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना विभाग लगातार सकारात्मक और प्रभावी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, विशाल सिंह के नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पत्रकार हितैषी बनी है।

प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि सूचना निदेशक के रूप में अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में विशाल सिंह ने पत्रकार कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पत्रकारों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

बाराबंकी का नियामतपुर वन क्षेत्र बनेगा ईको टूरिज्म हब, जंगलों के बीच पर्यटक लेंगे 'नेचर ट्रेल' का मजा

लखनऊ। पर्यटन विभाग राजधानी लखनऊ से 45 किलोमीटर की दूर बाराबंकी में नियामतपुर वन क्षेत्र को प्राकृतिक पर्यटन (ईको टूरिज्म) हब के रूप में विकसित करने में जुटा है। परियोजना का काम 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसमें पर्यटकों के लिए दो किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल विकसित की गई है, जहां प्रकृति प्रेमी घने वन क्षेत्र के बीच पैदल भ्रमण करते हुए समृद्ध जैव विविधता, विभिन्न प्रजातियों के पेड़-पौधों, पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का करीब से अनुभव कर सकेंगे। विभाग अगले पर्यटन सत्र में इसे पर्यटकों के लिए खोलने की रूपरेखा बना रहा है। परियोजना में 52.50 लाख रुपये की लागत से आधुनिक हाट, स्वच्छ शौचालय, आकर्षक सेल्फी प्वाइंट, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार और नाले पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया है। पूरे क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर वन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न पेड़-पौधों की प्रजातियों, उनकी विशेषताओं और पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझ सकेंगे।

कैंसर के खिलाफ यूपी की बड़ी जंग, योगी सरकार ने तैयार किया 10 साल का रोडमैप; हर मंडल में बनेगा आधुनिक सेंटर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक और समयबद्ध बनाने के लिए एक बड़ा विजन पेश किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर जिले तक कैंसर के इलाज की सुविधाएं विकसित करने और सड़क हादसों में घायल लोगों को 'गोल्डन ऑवर' (हादसे के बाद का पहला एक घंटा) के भीतर जीवनरक्षक इलाज देने के लिए प्रदेशव्यापी 'एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क' स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि राज्य की चिकित्सा प्रणाली को त्वरित उपचार, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और मजबूत रेफरल सिस्टम पर आधारित किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को इलाज के लिए भटकना न पड़े।

कैंसर के खिलाफ 10 साल का महा-रोडमैप

शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने 'उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स' की कार्ययोजना की समीक्षा की। बढ़ती जनसंख्या और जागरूकता की कमी के कारण कैंसर की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2026 से 2036 तक का 10 वर्षीय राज्य कैंसर रोडमैप तैयार किया है। यह मिशन मुख्य रूप से आठ स्तंभों पर काम करेगा, जिसमें रोकथाम, स्क्रीनिंग, डिजिटल रजिस्ट्री, ऑन्कोलॉजी रिसर्च और बच्चों के कैंसर (बाल्यावस्था कैंसर) के लिए सभी प्रमुख केंद्रों पर समग्र उपचार की सुविधाएं शामिल हैं।

हर मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र और डिजिटल ट्रैकिंग

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मंडलों में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं और जिला स्तर तक जांच सुविधाएं बढ़ाई जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) से लेकर जिला अस्पतालों तक नियमित स्क्रीनिंग होगी। मरीजों की पहचान से लेकर उनके इलाज और फॉलोअप की पूरी कमान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के हाथ में होगी। तंबाकू जनित कैंसर को रोकने के लिए स्वास्थ्य और आयुष विभाग मिलकर जागरूकता, खानपान और सुचारू जीवन पद्धति पर केंद्रित राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे।

युवा और महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, डिप्टी सीएम ने स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र युवाओं व महिलाओं की पहचान कर उनको प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। लाभार्थियों की रुचि व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद ऋण उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों का बैंकों से प्रभावी समन्वय स्थापित कराने के भी निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी कौशल के साथ-साथ साफ्ट स्किल, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता विकास तथा विपणन संबंधी प्रशिक्षण को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अभियान मिशन मोड में संचालित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, रेशम उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्पाद श्रेणी में ड्रेस डिजाइनिंग, अगरबत्ती, फुटबाल, बैग, बेकरी उत्पाद, पत्तों से बने पर्यावरण अनुकूल कप-प्लेट आदि लघु उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अलावा दोपहिया वाहनों की मरम्मत, रेडियो व टेलीविजन की मरम्मत, मोटर रिवाइंडिंग, विद्युत ट्रांसफार्मर की मरम्मत, सिंचाई पंपसेट की मरम्मत, ट्रैक्टर की मरम्मत, मोबाइल फोन मरम्मत, ब्यूटीशियन कोर्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर, डीटीपी जैसे रोजगारपरक प्रशिक्षण शामिल हैं।

सोलर आवर्स में गाड़ी चार्ज करना हुआ सस्ता, योगी सरकार ने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक टैरिफ में दी 20 फीसदी की राहत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बिजली उत्पादन, आपूर्ति और उपभोक्ता राहत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में बिजली दरें देश की सबसे न्यूनतम दरों में हैं, जबकि बिजली आपूर्ति देश की सर्वाधिक एवं सबसे बेहतर श्रेणी में है। इसके साथ ही योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और दिन के समय उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित सोलर आवर्स में 20 प्रतिशत टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इससे न केवल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा जोकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राम मंदिर ही नहीं अजमेर शरीफ दरगाह में भी हुई है दान चोरी, मौलाना ने वक्फ पर भी लगाया बड़ा आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। अयोध्या के राम मंदिर में कथित गबन की जांच के बीच अब मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के फंड को लेकर नया मामला सामने आया है। 'भारतीय समाज सेवक संगठन' के अध्यक्ष और चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक, मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में मिलने वाले जकात और वक्फ के दान का रुपया बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर मामले की जांच हो सकती है। तो फिर मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के फंड की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने कहा कि हाजी अली दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह सहित कई मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में जकात के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने दावा किया कि करीब 40 हजार करोड़ रुपये का जकात फंड अपने असली मकसद तक नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि यह पैसा गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की शिक्षा, इलाज और विकास पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन इसका इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने में किया गया। इसी वजह से समाज का गरीब वर्ग लगातार पिछड़ता गया और उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका।

मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राम मंदिर मामले में एसआईटी जांच के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह जकात और वक्फ फंड की भी जांच कराई जानी चाहिए। उनका मानना है कि धार्मिक दान जनता की आस्था से जुड़ा होता है। इसलिए उसके उपयोग में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। इधर, राम मंदिर में कथित गबन की जांच भी जारी है। जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, रिकॉर्ड में 79.85 लाख रुपये की चोरी दर्ज की गई है। वहीं जांच के दौरान कुछ लोगों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है। सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक लवकुश, अनुकल्प मिश्रा और राम शंकर यादव उर्फ टीनू यादव का नाम भी जांच में सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

संपादकीय

जापान की पीएम भारत आई तो एशिया का समीकरण बदला

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

जापान की पीएम सनाए तकाइची दिल्ली में गुरुवार को आयोजित भारत-जापान 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई। सवाल यह है कि भारत और जापान के रिश्ते कैसे हैं। तो इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जापान अगले दस सालों में भारत में करीब छै लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा साथ ही देश में जापानी कंपनियों की संख्या दुगुनी होगी। भारत में जापानी कंपनियों के माल को खूब पसंद किया जाता है। जापानी टैक्नोलॉजी है ही ऐसी कि उनका सामना भरोसेमंद माना जाता है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान की सनाए तकाइची ने 129 करार पर हस्ताक्षर किए। एशिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं, दो लोकतंत्र और दो टेक्नोलॉजी पावर। जब जापान के प्रधानमंत्री भारत की धरती पर उतरते हैं, तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं होता। ये इंडो-पैसिफिक के पावर बैलेंस की तस्वीर होती है।

भारत-जापान संबंध अब 'मित्रता' से आगे बढ़कर 'रणनीतिक जरूरत' बन चुके हैं। रिश्तों की नींवः बुद्ध से बुलेट ट्रेन तक- भारत-जापान का रिश्ता 1952 से है, पर इसकी जड़ें 1400 साल पुरानी हैं। जापान में बौद्ध धर्म भारत से ही गया।1958 तात्सुनो केस- जापान ने भारत को युद्ध के बाद पहली बार ODA यानी सरकारी सहायता दी। 2024ः भारत जापान का सबसे बड़ा ODA प्राप्तकर्ता है। 40 साल में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मिली है।

बुलेट ट्रेनः मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से। 508 किमी, 320 किमी/घंटा की रफ्तार। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, 'भरोसे का प्रोजेक्ट' है। जापान भारत को 'भरोसेमंद दोस्त' मानता है, क्योंकि भारत ने 1949 में जापान के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा वापस लेकर उसे फिर से खड़े होने में मदद की थी। आज के दौरे का एजेंडा- क्वाड + इंडो-पैसिफिक सुरक्षा- चीन का बढ़ता दबदबा दोनों के लिए चिंता है। जापान और भारत क्वाड के सदस्य हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज 'धर्म गार्डियन', नौसेना अभ्यास 'मालाबार' इसी का हिस्सा हैं। जापान भारत को US-2 उभयचर विमान और रक्षा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात कर रहा है। मकसदः 'एक आजाद, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक। आर्थिक साझेदारी- 'मेक इन इंडिया' को जापानी पावर- जापान भारत में 5वें सबसे बड़े निवेशक हैं। होंडा, सुजुकी, सोनी, तोशिबा, मित्सुबिशी पहले से हैं। नया फोकसः सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, स्टार्टअप। जापान ने अगले 10 साल में भारत में 10 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट इसी का उदाहरण है। टेक्नोलॉजी और स्किल-

जापान को 2030 तक 80 लाख कुशल वर्कर्स की जरूरत है। भारत की युवा आबादी वहां समाधान है। 'टाइटल स्किल वीजा' और 'स्पेसिफाइड स्किल वर्कर' समझौते से लाखों भारतीय जापान में नौकरी करेंगे। बदले में जापान रोबोटिक्स, AI, 6G, बुलेट ट्रेन देगा। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर- नॉर्थ-ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट- सब में जापानी पैसा और क्वालिटी। जापान का मॉडलः 'कर्ज नहीं, क्वालिटी इंफ्रा। सांस्कृतिक और पीपल-टू-पीपल- एनीमे से योग तक। जापानी छात्र वाराणसी पढ़ने आते हैं, भारतीय छात्र टोक्यो में AI सीखते हैं। ये 'सॉफ्ट पावर' रिश्ते को लंबे समय तक जिंदा रखता है।

रिश्ते में चुनौती क्या है? जापानी कंपनियां नियम, जमीन अधिग्रहण और लालफीताशाही से परेशान होती हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी जमीन की वजह से लेट हुआ। जापान चीन के साथ भी 350 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। भारत के साथ वो चीन को 'रिप्लेस' नहीं कर सकता, सिर्फ 'रिस्क कम' कर सकता है। जापान का संविधान हथियार निर्यात को सीमित करता है। इसलिए भारत को बड़ी डील मिलने में देर होती है। तो इस दौरे का मतलब क्या निकला? जब जापान की पीएम भारत आती हैं, तो वो 3 संदेश देती हैं- चीन को संदेशः एशिया में तुम अकेले नहीं हो। भारत-जापान मिलकर बैलेंस बनाएंगे।

भारत को संदेशः हम आपके विकास में लॉन्ग-टर्म पार्टनर हैं। पैसा, टेक और स्किल सब देंगे।

दुनिया को संदेशः लोकतंत्र, कानून का राज और फ्री ट्रेड वाला मॉडल ही भविष्य है। रिश्ता अब 'रोमांस' नहीं, 'रणनीति' है। पहले भारत-जापान का रिश्ता भावनात्मक था- बुद्ध, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। अब वो पूरी तरह प्रैग्मैटिक है - सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, सुरक्षा। जापान को भारत चाहिए ताकि वो चीन पर निर्भरता घटाए। भारत को जापान चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी में छलांग लगाए और मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसलिए जब जापान की पीएम भारत आती हैं, तो वो सिर्फ हाथ नहीं मिलातीं। वो एशिया के भविष्य का नक्शा साथ लाती हैं। और उस नक्शे का सेंटर पॉइंट हैः भारत-जापान। 'भारत-जापानः साझा भविष्य की साझा जिम्मेदारी' है।

भारत जापान की नई रणनीतिक साझेदारी से मजबूत होते आर्थिक संबंध

भारत और जापान के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि वे रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक साझेदारी के मजबूत आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका आत्मीय स्वागत और उन्हें अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित करना केवल एक शिष्टाचार नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच विकसित हुए विश्वास, सम्मान और मित्रता का प्रतीक भी है। यही कारण है कि इस यात्रा को भारत और जापान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। भारत और जापान आज एशिया की दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। दोनों देशों की सोच मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण पर केंद्रित है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में जब आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा, नई तकनीक और रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ रहा है तब भारत और जापान की साझेदारी और अधिक प्रासंगिक हो गई है। दोनों देश नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं तथा आर्थिक विकास को साझा समृद्धि का माध्यम मानते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले दस वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन अर्थात लगभग छह लाख करोड़ रुपये के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह निवेश सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इतनी बड़ी निवेश योजना भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। इससे भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की हर तीन में से दो कारें भारत में बन रही हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि जापानी कंपनियां भारत की उत्पादन क्षमता, कुशल मानव संसाधन और विशाल बाजार पर भरोसा कर रही हैं। भारत में निर्मित इन वाहनों का निर्यात सौ से अधिक देशों में किया जा रहा है जिससे भारत वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्यात के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। यह सफलता दोनों देशों के औद्योगिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जापान की प्रधानमंत्री ने भारत में लगभग एक हजार बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। यह पहल केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती नहीं देगी बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती को भी बढ़ावा देगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने में सहायता मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में यह साझेदारी भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत और जापान ने रक्षा सहयोग को भी नई ऊंचाई देने का निर्णय लिया है। दोनों देश नौसेना के लिए आधुनिक यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना प्रणाली का संयुक्त विकास करेंगे। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। यह साझेदारी केवल दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई तकनीकों के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और निवेश से भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। वैश्विक स्तर पर चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत भारत और जापान मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इससे दोनों देशों की औद्योगिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में वृद्धि होगी।

भारत और जापान के बीच व्यापार लगातार विस्तार कर रहा है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का वार्षिक व्यापार हो रहा है और जापान भारत में निवेश करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। भारत से जापान को ऑर्गेनिक रसायन, वाहन, ऑटो पार्ट्स, धातु उत्पाद, समुद्री खाद्य पदार्थ और रत्न आभूषण का निर्यात किया जाता है जबकि जापान से भारत में भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, तांबा, प्लास्टिक और अत्याधुनिक औद्योगिक उपकरण आयात किए जाते हैं। यह व्यापारिक संतुलन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे का पूरक बनाता है। दोनों देशों ने भविष्य में भारतीय रुपये और जापानी येन में सीधे व्यापार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा विनिमय का खर्च घटेगा, भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और दोनों देशों की कंपनियों को व्यापार करने में अधिक सुविधा मिलेगी। यह आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने वाला दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। भारत में जापानी निवेश की सबसे बड़ी पहचान मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है। जापान की शिनकानसेन तकनीक और जापानी वित्तीय सहयोग से तैयार हो रही यह परियोजना भारत के परिवहन इतिहास में नई क्रांति लाने वाली है। यह केवल तेज गति की रेल सेवा नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग, तकनीकी हस्तांतरण, कौशल विकास और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग का प्रतीक भी है। इस परियोजना से भारत को विश्वस्तरीय रेल तकनीक प्राप्त होगी और भविष्य की अनेक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। राजस्थान का नीमराना आज भारत में जापानी औद्योगिक सहयोग का सबसे सफल उदाहरण बन चुका है।

यहां अनेक जापानी कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और हजारों भारतीयों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजनाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले वर्षों में जापानी निवेश और तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी तथा स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जापानी निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था शुरू करने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। इससे निवेशकों को सीधे उच्च स्तर पर संवाद का अवसर मिलेगा और निवेश संबंधी बाधाओं का शीघ्र समाधान संभव होगा। यह कदम भारत को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत और जापान की मित्रता अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है बल्कि यह विश्वास, साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों पर आधारित व्यापक साझेदारी का स्वरूप ले चुकी है। दोनों देशों का लक्ष्य तकनीक, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। बढ़ता निवेश, विस्तृत व्यापार, आधुनिक परियोजनाएं और साझा रणनीतिक दृष्टि भारत और जापान की मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मजबूत आधार बन चुकी है। **कांतिलाल मांडोत**

सुल्तानपुर में बीसी सखी योजना की डिजिटल क्रांति से ग्रामीण स्वावलंबन और महिला आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम

उत्तर प्रदेश में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) सखी योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित हो रही है। इस दूरदर्शी पहल ने न केवल गांवों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को अत्यंत सुगम बनाया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है। डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और महिला स्वावलंबन के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावी कदम सिद्ध हुई है। योजना के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित महिलाएं अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर वित्तीय लेनदेन, पेंशन वितरण, सरकारी योजनाओं के लाभ का हस्तांतरण और जमा-निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत सुगमता से कर रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और महिलाओं को बैंक के चक्कर लगाने तथा लंबी लाइनों में खड़े होने की असुविधा से मुक्ति मिली है। इस व्यवस्था से ग्रामीणों के समय और धन दोनों की बचत हो रही है। यह योजना ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के भीतर छिपी उद्यमशीलता और नेतृत्व क्षमता को बाहर लाने में पूरी तरह सफल रही है।

तकनीक से जुड़कर लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्वाइप मशीनों का संचालन करने वाली ये महिलाएं अब अपने परिवारों की मुख्य आर्थिक संबल बन चुकी हैं। नियमित आय और लाभांश के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं। गांव के भीतर उनका सामाजिक सम्मान बढ़ा है और वे आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही हैं।

इसी सफल नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड मोतिगरपुर की ग्राम पंचायत डींगुरपुर बनकेगांव की निवासी श्रीमती सुषमा गुप्ता आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। कभी एक सामान्य गृहणी के रूप में घर-परिवार तक सीमित रहने वाली सुषमा जी ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आया परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि यदि महिलाओं को सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे समाज और परिवार दोनों की दिशा बदल सकती हैं। बी.ए. तक शिक्षित सुषमा जी वर्ष 2017 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। उस समय परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए उनके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वे भी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दें।

समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने छोटे-मोटे लेन-देन शुरू किए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। बैठकों में भाग लेने से उन्हें अन्य महिलाओं के अनुभव सुनने का मौका मिला और यह विश्वास पैदा हुआ कि महिलाएं चाहें तो अपनी मेहनत से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। वर्ष 2021 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बी.सी. सखी के रूप में चयनित होने का अवसर मिला, जो उनके लिए आत्मसम्मान और पहचान का नया रास्ता बना। शासन द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ही गांव में बैंकिंग सेवा केन्द्र शुरू किया।

शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग के प्रति कम जागरूकता होने के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सुषमा जी ने धैर्य और लगन से घर-घर जाकर महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों को बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक किया, जिससे धीरे-धीरे शासन की इस व्यवस्था पर ग्रामीणों का भरोसा बढ़ता चला गया। आज उनका केन्द्र गांव में विश्वास और सुविधा का प्रतीक बन चुका है। बी.सी. सखी के रूप में सुषमा जी ग्रामीणों को धन जमा करने, निकासी करने, बचत खाता खोलने और जीवन बीमा जैसी आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर ही उपलब्ध करा रही हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जरूरत पड़ने पर वृद्धों, विधवा महिलाओं और मनरेगा मजदूरों के घर जाकर भी वित्तीय सेवाएं देती हैं, जिन्हें पहले पैसे निकालने के लिए कई किलोमीटर दूर बैंक शाखा तक जाना पड़ता था।

अब ग्रामीणों को लंबी लाइनों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। सुषमा जी का सम्मानजनक व्यवहार और ईमानदारी ग्रामीणों के बीच उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। इस कार्य से होने वाली नियमित आय से वे अपने पति श्री अमित कुमार गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बच्चों की शिक्षा व घरेलू खर्चों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। सुषमा जी की यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सुल्तानपुर के ग्रामीण समाज में शासन की नीतियों से हो रहे सकारात्मक परिवर्तन की कहानी भी है। वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संदेश देती हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिसमें एक कदम बढ़ाने पर प्रशासन पूरी तरह साथ खड़ा रहता है। उनका यह सफरनामा संघर्ष, आत्मविश्वास और शासकीय अवसरों के कुशल उपयोग का एक उदाहरण होने के साथ-साथ हर उस ग्रामीण महिला को प्रेरित करता है जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देखती है। **जनपद -सुलतानपुर**

दैनिक राशिफल

मेषः रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग रहेगा। **लवः** रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ रंगः लाल 7 **शुभ अंकः** 9

वृषभः आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्च बढ़ सकता है। धैर्य से काम लें, विवाद से बचें।
लवः जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंगः सफेद 7 **शुभ अंकः** 6

मिथुनः नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।
लवः प्रेम संबंध मजबूत होंगे। **शुभ रंगः** हरा 7 **शुभ अंकः** 5

कर्कः कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
लवः जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। **शुभ रंगः** चांदी 7 **शुभ अंकः** 2

सिंहः भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा।
लवः रिश्तों में खुशियां आएंगी। **शुभ रंगः** सुनहरा 7 **शुभ अंकः** 1

कन्याः निवेश सोच-समझकर करें। किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है। संयम रखें। **लवः** बातचीत में संयम रखें। **शुभ रंगः** हरा 7 **शुभ अंकः** 5

तुलाः दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। **लवः** प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
शुभ रंगः गुलाबी 7 **शुभ अंकः** 6

वृश्चिकः विरोधियों से सावधान रहें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। **लवः** रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। **शुभ रंगः** लाल 7 **शुभ अंकः** 9

धनुः शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और संतान से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। **लवः** प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। **शुभ रंगः** पीला 7 **शुभ अंकः** 3

मकरः परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
लवः जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंगः नीला 7 **शुभ अंकः** 8

कुंभः आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे-छोटे प्रयास बड़े लाभ दिला सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। **लवः** संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
शुभ रंगः आसमानी 7 **शुभ अंकः** 4

मीनः आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें।
लवः परिवार और साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। **शुभ रंगः** पीला 7 **शुभ अंकः** 3

आज का उपायः भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें तथा जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।

प्रदेश सरकार ने भिक्कावाला पंप नहर का आधुनिक तकनीक से किया पुनरोद्धार

लखनऊः उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की रामगंगा-फिका दोआब क्षेत्र में स्थित भिक्कावाला पंप नहर आज केवल एक सिंचाई संरचना नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता, आधुनिक इंजीनियरिंग और किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का जीता-जागता प्रतीक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित यह परियोजना - जो दशकों की बाढ़, सिल्टेशन और संरचनात्मक क्षति के कारण लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी, को वर्तमान सरकार ने एक व्यापक पुनरुद्धार अभियान के माध्यम से न केवल पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसे एक सफल इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में भी स्थापित किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः वीर सैनिकों के लिए एक वचन

भिक्कावाला पंप नहर की स्थापना के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और सम्मानजनक उद्देश्य था। यह परियोजना मूल रूप से उन भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित थी, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की और सेवानिवृत्ति के बाद कृषि कार्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर आकर बसे। उस समय यह सुनिश्चित किया गया कि इन वीर जवानों के खेतों को सिंचाई हेतु जल मिले। इस योजना के मूल मंत्र में यह नहर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले थी। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया गया। इस परियोजना की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1972 में की गई, इसके बाद वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। दोनों चरणों को एक एकीकृत जलीय तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जो मिलकर बिजनौर जिले की सबसे जटिल पंप-आधारित सिंचाई प्रणालियों में से एक बनाते हैं।

जनपद बिजनौर के इस्लामनगर ग्राम पंचायत में स्थित इस परियोजना की भौगोलिक स्थिति भी इसे विशेष बनाती है। रामगंगा फिका दोआब नहर के जल को उठाकर कृषकों को सिंचाई हेतु दूरस्थ खेतों तक जलापूर्ति उपलब्ध कराने के चुनौतीपूर्ण कार्य को आधुनिक मशीनों एवं यंत्रों की सहायता से संपादित करने का कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है जिससे कृषकों को निर्बाध जल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।

तकनीकी संरचनाः एक परिष्कृत जल-वितरण प्रणाली

भिक्कावाला पंप नहर एक हाइब्रिड हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पर संचालित होती है- एक ऐसी प्रणाली जो जल को पंप करके 12 किलोमीटर से अधिक लंबे नहर नेटवर्क के माध्यम से वितरित करती है। नहर प्रणाली दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण की जल प्रवाह क्षमता 25 क्यूसेक है, जबकि द्वितीय चरण की क्षमता 12.5 क्यूसेक है। पूरे तंत्र में 60 हॉर्स पावर के शक्तिशाली सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाए गए हैं। निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण में दो सक्रिय पंप और एक स्टैंडबाय पंप, तथा द्वितीय चरण में एक सक्रिय और एक स्टैंडबाय पंप है ताकि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में जल आपूर्ति बाधित न हो।

भिक्कावाला पम्प नहर से कुल नहर नेटवर्क लगभग 12.24 किलोमीटर में फैला है। इस नेटवर्क में रसूलपुर, जामुनवाला और पाथरावाला जैसी महत्वपूर्ण माइनर संरचनाएं शामिल हैं जो जल को खेतों के अंतिम छोर (टेल एंड) तक पहुंचाती हैं। प्रथम चरण में 6.64 किमी0 की वितरण नहरें और 4.30 किमी लंबी अफजलगढ़ मुख्य नहर शामिल हैं, जबकि द्वितीय चरण में 5.60 किमी की नहर प्रणाली है।

जब थम गई जल की धारा

अपनी समस्त इंजीनियरिंग श्रेष्ठता के बावजूद भिक्कावाला पंप नहर प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों से अछूती नहीं रही। वर्षों तक भारी बारिश, बार-बार आने वाली बाढ़ ने नहर की संरचनात्मक अखंडता को गंभीर क्षति पहुंचाई। नहर की लाइनिंग के साथ लगाई गई बोल्डर पिचिंग कई स्थानों पर टूट-बिखर गई थी। ब्रिक लाइनिंग कई खंडों में ध्वस्त हो चुकी थी जिससे जल का रिसाव और बर्बादी हो रही थी। डिलीवरी टैंक में खराबी आने से वितरण तंत्र बाधित हो गया था, और चेकवॉल तथा क्यू-नेट वॉल की हालत भी जर्जर हो गई। परिणामस्वरूप नहर का पानी टेल एंड तक नहीं पहुंच पा रहा था और दूरस्थ खेतों के किसान सिंचाई से वंचित हो रहे थे। स्थिति को और कठिन बनाते हुए, पंप स्टेशन पर कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर भी इतने जर्जर हो गए थे कि चौबीस घंटे संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो चला था। समग्र रूप से, पूरी प्रणाली अपनी क्षमता की सीमा से परे जर्जर हो चुकी थी।

पुनरुद्धारः एक त्रिआयामी नवीनीकरण

नहर की इन समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने एक व्यापक आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों क्षेत्रों में एक साथ क्रांतिकारी सुधार आरम्भ किये गये। मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल कायाकल्प के अन्तर्गत पुराने और जीर्ण पंपों की जगह नए 12.5 क्यूसेक पंप सेट, उन्नत इंडक्शन मोटर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए जो अधिक दक्षता और कम ऊर्जा खपत के साथ कार्य करते हैं। जर्जर पाइपिंग को नई पाइपलाइन से बदला गया और सुरक्षा के लिए जीआई चेन लिंक फेंसिंग लगाई गई। परिसर में एलईडी स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाए गए जिससे बिजली पर निर्भरता कम हुई। सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए, जिससे महत्वपूर्ण कृषि अवसंरचना की चौबीस घंटे निगरानी की जा सके।

सिविल एवं संरचनात्मक जीर्णोद्धार के अन्तर्गत सिविल इंजीनियरिंग के मोर्चे पर भी कार्य उतना ही व्यापक था। नहर चैनलों में जहां ब्रिक लाइनिंग टूट गई थी, उसे नए सिरे से बनाया गया। बोल्डर पिचिंग की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। डिलीवरी टैंक को 0.5 मी0 उठाया गया, चेक वॉल और क्यू-नेट वॉल का संपूर्ण जीर्णोद्धार किया गया। द्वितीय चरण में किलोमीटर 1.741 से किलोमीटर 5.600 तक नहर की री-सेक्शनिंग की गई। यह 3.86 किलोमीटर का हस्तक्षेप उस खंड को नया जीवन देने वाला सिद्ध हुआ जो पहले सबसे अधिक क्षतिग्रस्त था। कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों की भी मरम्मत की गई ताकि संचालन दल के लिए उचित कार्य-

परिस्थितियां सुनिश्चित हो सकें। रूपये 367.86 लाख की लागत की इस पुनरुद्धार परियोजना को 31 मार्च 2026 की निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कर लिया गया- यह तथ्य अपने आप में नियोजन और क्रियान्वयन की गुणवत्ता का प्रमाण है। लगभग 1,110 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की बहाली से बेहतर फसल उत्पादन, भूजल पर कम निर्भरता और 1,247 किसान परिवारों के लिए अधिक सुरक्षित कृषि चक्र के उत्पादन का लाभ मिला है।

पानी से परे, एक नई उम्मीद

किसानों की हितैषी योगी सरकार ने भिक्कावाला नहर का पुनरुद्धार केवल एक सफल अवसंरचना परियोजना ही नहीं है बल्कि इसका प्रमाण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में पुरानी सिंचाई प्रणालियों को अप्रचलित मानकर छोड़ा नहीं बल्कि लक्षित निवेश और तकनीकी दक्षता से उन्हें पूरी क्षमता के साथ पुनर्जीवित किया है, और उनकी मूल क्षमता से भी अधिक बेहतर बनाया गया है। बिजनौर के इस्लामनगर ग्राम पंचायत और आसपास के रामगंगा-फिका दोआब क्षेत्र के किसानों के लिए यह नहर वरदान साबित हुई है। इस नहर से पानी समय पर उनके खेतों तक पहुंचता है। अब सूखे मौसम में उनकी फसल नहीं मरेगी। भिक्कावाला पंप नहर में आज केवल रामगंगा का जल लेकर नहीं बहती-वह विश्वास, तकनीक और समृद्धि की एक सतत धारा बहाती है। यह नहर हर खेत को पानी के संकल्प की दिशा में एक सच्चा और प्रेरणादायक मील का पत्थर साबित हुई है। **-अभिषेक सिंह**

पाकिस्तान में भड़कता आंतरिक विद्रोह

पाकिस्तान में इन दिनों अंदरूनी हालात काफी खराब चल रहे हैं। एक ओर पाकिस्तानी हुकूमत देश में बेकाबू होती महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, तो दूसरी ओर वर्षों से जबरन कब्जा किए हुए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी का बिगुल बजा दिया है। इससे पाकिस्तानी हुकूमत अपने ही देश में दो तरफ़ा घिरी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान वर्षों से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने में देश के विकास की बड़ी राशि खर्च करता आया है। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को छोड़कर समूचे देश में अस्थिरता और असंतोष का माहौल दिखाई देता है।

बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना और हुकूमत ने अपनी सीमाओं से लगे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे क्षेत्रों का बंदूक के बल पर अपने राज्य में विलय तो करवा लिया, लेकिन इन क्षेत्रों में लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध असंतोष बना हुआ है। आज भी इन क्षेत्रों में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन समय-समय पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के विरुद्ध इन क्षेत्रों में लंबे समय से संघर्ष जारी है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद को भी बड़ा झटका लगा है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न आतंकी गुट अपने-अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन, धार्मिक नेता और आतंक के सरगना एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान में बढ़ी हत्याओं और आतंकी घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि जिन तत्वों को कभी दूसरे देशों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, वही आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आतंकवाद का वही बीज अब विशाल वटवृक्ष बनकर पाकिस्तान की सत्ता और उसे संरक्षण देने वालों के लिए संकट का कारण बन गया है।

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पर कार्रवाई तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। आम जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने वाला कोई मजबूत नेतृत्व दिखाई नहीं देता। जो राजनीतिक दल कभी एक-दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वे आज सत्ता के समीकरणों के कारण साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की सुध लेने वाला कोई प्रभावी नेतृत्व दिखाई नहीं देता। विदेशों में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना आज़ादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लोगों के आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। किंतु यदि जनता का असंतोष और सरकार की कठोर नीतियाँ इसी प्रकार जारी रहीं, तो पाकिस्तान के सामने भविष्य में और भी गंभीर आंतरिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

अरविंद रावल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिल रही खाद, धान रोपाई के बीच बढ़ी किसानों की परेशानी

लालगंज (रायबरेली)। धान रोपाई के मौसम में फार्मर रजिस्ट्री न होने से क्षेत्र के कई किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उधर, अघोषित बिजली कटौती और नहरों में पर्याप्त पानी न होने से खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद और सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने से धान की रोपाई प्रभावित हो सकती है। ऐहार गांव के रामचरन यादव, बबलू, रामकृष्ण, राम आसरे शर्मा, संजीव, नवल किशोर, अंशु यादव और राजाराम ने बताया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के समितियों से खाद नहीं दी जा रही है। इससे उन्हें काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है।किसानों ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती के कारण बोरिंग से भी पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं नहरों में भी पर्याप्त पानी नहीं है। इससे खेती का संकट और गहरा गया है। कृषि रक्षा इकाई के प्रभारी आशीष प्रकाश ने बताया कि जिन किसानों का किसी कारण खतौनी में नाम दर्ज नहीं है, उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि, राजस्व और विकास विभाग की संयुक्त टीम गांव-गांव शिविर लगाकर खतौनी में अंश निर्धारण और अन्य जरूरी सुधार करा रही है।

प्लग लगाते समय महिला को लगा करंट, गंभीर हालत

लालगंज (रायबरेली): क्षेत्र के ऊगाभाद गांव में शुक्रवार को पंखे का प्लग लगाते समय 36 वर्षीय महिला करंट की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने तत्काल बिजली की एमसीबी बंद कर महिला को करंट से अलग किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी पिंकी (36) पत्नी अजीत घर में पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा रही थीं। बताया जा रहा है कि पंखे का तार कटा हुआ था। प्लग लगाते ही वह करंट की चपेट में आ गई और कुछ देर तक तार से चिपकी रहीं। महिला को करंट से चिपका देख परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत एमसीबी बंद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। परिजनों ने आनन-फानन में पिंकी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. गौरव पांडेय ने बताया कि महिला का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

श्रीमद्भागवत कथा से मिलता है भगवान की कृपा का आशीर्वाद : चैतन्य जी महाराज

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बाईपास रोड स्थित एक उत्सव लॉन में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथा व्यास वृंदावन से पधारे चैतन्य जी महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। इसके श्रवण से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कथा व्यास ने कहा कि श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रीमद्भागवत कथा सुनने मात्र से जीव पापों से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है। कथा श्रवण करने वाले भक्तों पर भगवान नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग अपनाकर ही मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। कथा के दौरान भजनों और प्रवचनों से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण किया।आयोजक मंडल के दीपप्रकाश शुक्ला ने बताया कि कथा का आयोजन प्रतिदिन शाम छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक किया जा रहा है। सात जुलाई को कथा का समापन होगा। आठ जुलाई को विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर रामस्वरूप यादव, बराती लाल यादव, हनुमान यादव, रामचंद्र मिश्रा, बलराम, राजन यादव, मुन्ना, सुंदरलाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

यूपीटीईटी-2026: भदोही में 95.15 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा

भदोही। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 शुक्रवार को जनपद के सात परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई। दोनों पालियों को मिलाकर 95.15 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 298 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में कुल 3072 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2905 उपस्थित रहे और 167 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार प्रथम पाली में 94.56 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं द्वितीय पाली में 3072 अभ्यर्थियों में से 2941 ने परीक्षा दी, जबकि 131 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस पाली में 95.74 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 6144 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 5846 ने परीक्षा दी, जबकि 298 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जनपद के सात परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

महाकुंभ-2025 को नवाचार हेतु मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

● महाकुंभ ने दुनिया के सामने भारत की विरासत और डिजिटल सामर्थ्य का किया अद्भुत प्रदर्शन- मंत्री ए.के. शर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ-2025 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, आधुनिक तकनीक आधारित प्रबंधन और सुशासन की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि महाकुंभ-2025 अनेक मायनों में दिव्य, भव्य, अद्भुत और विलक्षण आयोजन रहा। इस आयोजन ने न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को विश्व के सामने गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और कुशल प्रशासन के माध्यम से विकसित भारत की नई तस्वीर भी दुनिया को दिखाई। शर्मा ने कहा कि महाकुंभ 2025 को इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा स्वच्छता-उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब केंद्र सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश ने आयोजन, प्रबंधन, स्वच्छता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि जब महाकुंभ की तैयारियां प्रारंभ हुई थीं, तभी यह स्पष्ट किया गया था कि यह महाकुंभ डिजिटल होगा, आधुनिक तकनीक से संचालित होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान ने उस संकल्प पर भारत सरकार की भी मुहर लगा दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणा और सतत दिशा-निर्देश को देते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।उन्होंने महाकुंभ-2025 के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, स्वच्छता कर्मियों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक कर्मयोगी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम ने इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर एक अनुकरणीय मॉडल बनाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आगे भी सुशासन, डिजिटल नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

सम्पर्क सूत्र- प्रवीण मालवीय

विभिन्न जनपदों के कुल 35 मार्गो के चालू कार्यो हेतु 28 करोड़ 73 लाख 07 हजार की अवशेष धनराशि की गयी अवमुक्त

लखनऊ: उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 35 मार्गो के स्वीकृत एवं चालू कार्यो हेतु 28 करोड़ 73 लाख 07 हजार रूपए की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2027 तक कर लिया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2027 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट हर माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सम्पर्क सूत्र-अभिषेक सिंह

प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा में बनेगा एक आदर्श पशु चिकित्सालय

● आधुनिक उपकरणों से लैस पशुचिकित्सालय पर पशुओं के सभी रोगों के निदान की उपलब्ध होगी नवीनतम सुविधाएं-धर्मपाल सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा 26 नवम्बर, 2025 को जारी नवीन गाइडलाइन के अनुसार नवीन व आधुनिक आधारभूत संरचना, समस्त आधुनिक उपकरण से लैस पशु चिकित्सालय पर पशुओं के सभी प्रकार के रोगों के निदान की नवीनतम सुविधायें उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त इन आदर्श पशु चिकित्सालयों में अन्तःरोगी विभाग (वार्ड) की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें रोगी पशु को सघन उपचार हेतु भर्ती किया जा सकेगा। यह जानकारी प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने देते हुए बताया कि प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय पर नवीन व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में एक पशु चिकित्साधिकारी के स्थान पर दो पशु चिकित्साधिकारी, दो वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट तथा दो वेटेरिनरी अटेंडेंट मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध रहेंगे, जो क्षेत्र के समस्त पशुपालकों को उच्च गुणवत्तापरक उपचार एवं मार्डन डायग्नोसिस की सुविधायें प्रदान करेंगे।

इन पशु चिकित्सालयों के निर्माण संबंधी चयन के संबंध में सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा स्थान की संस्तुति प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के समस्त संस्थाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करते हुये, प्रदेश के समस्त पशुपालक भाइयों को पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान एवं बांझपन चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण इत्यादि की सेवा प्रदान करने तथा निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु पूर्णतया वचनबद्ध हैं।

सम्पर्क सूत्र- निधि वर्मा

प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों पर अंतर्जनपदीय विशेष प्रवर्तन अभियान का संचालन

● विशेष प्रवर्तन टीमों द्वारा कुल 362 निर्माण इकाइयों का किया गया निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रदेशवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं मानक गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाइयों पर अंतर्जनपदीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त मण्डलों के मण्डलीय सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में गठित विशेष प्रवर्तन टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित 362 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया।

अभियान के दौरान 233 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन का गहन परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 56 निर्माण इकाइयों को सुधार सूचना जारी की गई। जांच में 38 इकाइयाँ लम्बे समय से बंद, 21 इकाइयाँ स्थापना प्रक्रिया में तथा 38 इकाइयों द्वारा लाइसेंस सरेंडर किए जाने की स्थिति पाई गई। इसके अतिरिक्त 41 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किये गए। ऐसी 57 विनिर्माण इकाइयाँ, जिनके द्वारा निरीक्षण न करा कर अपितु इकाई को बंद किया गया, उन इकाइयों पर नोटिस चस्पाकर सील कर दिया गया कि बिना निरीक्षण कराये इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाये तथा 37 इकाइयों को पाई गयी गंभीर कमियों के कारण उनमे उत्पादन बंद कराया गया। समग्र कार्यवाही में पाई गयी कमियों के आधार पर कुल 293 किलो लीटर र्च्व को सीज किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 5.06 लाख रूपये है। इस विशेष अभियान के दौरान निर्माण परिसर की स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, वदंजपवद तथा त्व् की उपलब्धता तथा क्रियाशीलता, खाद्य संचालकों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विनिर्माण प्रक्रिया, उपकरणों की स्वच्छता, पैकेजिंग सामग्री, लेबलिंग, अभिलेखों का संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के अनुपालन का भी विस्तृत परीक्षण किया गया।

सम्पर्क सूत्र- आशिया खातून

महापुरुषों की प्रतिमाएं राष्ट्र की चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत हैं-जयवीर सिंह

● विगत 05 वर्षों के दौरान विभिन्न जनपदों में लगभग 43 महापुरूषों, राष्ट्रनायकों एवं संत महात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित की गयी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके महापुरुषों, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति से होती है। प्रतिमाएँ केवल कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं होतीं, बल्कि वे राष्ट्र की सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक चेतना की जीवंत प्रतीक हैं। सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ये प्रतिमाएँ नई पीढ़ी को निरंतर यह संदेश देती हैं कि महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन से राष्ट्र और समाज के लिए किन आदर्शों की स्थापना की। यही कारण है कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाकर उन्हें जन-जन की प्रेरणा का स्रोत बना रही है। जयवीर सिंह ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 43 महापुरुषों, राष्ट्रनायकों एवं संत-महात्माओं की प्रतिमाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 14 प्रतिमाएँ पूर्ण होकर स्थापना के लिए तैयार हैं, जिन्हें आगामी एक-दो माह में स्थापित किया जाएगा। वहीं 17 अन्य प्रतिमाओं के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्री ने बताया कि वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की साढ़े बारह फीट ऊँची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाएँ एटा, बलिया, फिरोजाबाद तथा सिरसागंज (मैनपुरी) सहित विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जा चुकी हैं। वाराणसी एवं मुरादाबाद में उनकी प्रतिमाएँ स्थापना के लिए तैयार हैं, जबकि देवलास (मऊ) एवं बाराबंकी में उनका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी प्रकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज तथा रानी लक्ष्मीबाई की साढ़े बारह फीट ऊँची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाओं की स्थापना भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फीट ऊँची भव्य प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और लोकसेवा के आदर्शों का संदेश देती हैं। प्रयागराज में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा मैनपुरी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएँ भी स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की साढ़े बारह फीट ऊँची प्रतिमा गोरखपुर हवाई अड्डे पर स्थापित किए जाने हेतु तैयार है। सरदार वल्लभभाई पटेल की साढ़े बारह फीट ऊँची प्रतिमाएँ प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर में स्थापित की जाएँगी। मेरठ में अमर शहीद मंगल पांडेय, वाराणसी में संत कबीरदास एवं उनके पाँच प्रमुख शिष्यों, मैनपुरी में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर एवं दानवीर भामाशाह, अयोध्या, चित्रकूट एवं मैनपुरी में महर्षि वाल्मीकि, तथा एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, औरैया एवं सीतापुर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह की छह फीट ऊँची प्रतिमाओं का निर्माण एवं स्थापना का कार्य कराया गया है अथवा प्रगति पर है।

वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा बाँदा में स्थापित हो चुकी है तथा रायबरेली एवं आगरा में उनका निर्माण कार्य चल रहा है। जयवीर सिंह ने बताया कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्रीराम एवं निषादराज के ऐतिहासिक मिलन को दर्शाती 51 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता, समानता और आत्मीयता के शाश्वत संदेश का प्रतीक होगी। बहराइच के चित्तौरा स्थित स्मारक परिसर में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊँची अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। वाराणसी में संत गुरु रविदास की प्रतिमा तथा चित्रकूट में श्रीरामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास की लगभग साढ़े बारह फीट ऊँची भव्य प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। वहीं महाराजा सूरजमल की प्रतिमा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थापित की जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल प्रतिमाओं की स्थापना करना नहीं, बल्कि उन महापुरुषों के विचारों, आदर्शों और जीवन मूल्यों को समाज में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक सशक्त केंद्र बनकर उभरा है और भविष्य में भी महापुरुषों की स्मृतियों के संरक्षण तथा उनके आदर्शों के व्यापक प्रसार का यह अभियान पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रनायकों, संत-महात्माओं एवं महान विभूतियों के सम्मान तथा उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना का अभियान इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिमाओं का निर्माण कराना नहीं, बल्कि समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रभक्ति, त्याग, शौर्य, सामाजिक समरसता और लोकसेवा के आदर्शों से जोड़ना है।

सम्पर्क सूत्र- केवल

हमारी विद्युत दरें देश में न्यूनतम, हमारी विद्युत आपूर्ति देश में अधिकतम- ए. के. शर्मा

● लगातार सातवें वर्ष न्यूनतम बिजली दरों के साथ अधिकतम विद्युत आपूर्ति दे रहा उत्तर प्रदेश,

ऊर्जा प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान

32,673 मेगावाट आपूर्ति के साथ उत्तर प्रदेश ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत दरें देश की सबसे न्यूनतम दरों में हैं, जबकि विद्युत आपूर्ति देश की सर्वाधिक एवं सबसे बेहतर श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।उन्होंने बताया कि लगातार सातवें वर्ष भी प्रदेश में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए देय टैरिफ को यथावत रखा गया है। यह निर्णय सरकार की जनकल्याणकारी सोच तथा गरीबों, किसानों, घरेलू एवं अन्य उपभोक्ताओं के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने तथा दिन के समय उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निर्धारित सोलर आवर्स में 20 प्रतिशत टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। इससे न केवल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में प्रतिदिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रदेश ने 32,673 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय तापीय विद्युत उत्पादन मात्र 5,180 मेगावाट तक सीमित था, जबकि आज प्रदेश सौर ऊर्जा से ही इससे अधिक उत्पादन कर रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता सोलर पार्कों से तथा लगभग 2,500 मेगावाट क्षमता प्रधानमंत्री

सूर्य घर योजना के माध्यम से विकसित की जा रही है। इसके साथ ही मिर्जापुर एवं मेजा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तापीय विद्युत परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है तथा पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है। पहले जहां ये संयंत्र लगभग 65 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर संचालित होते थे, वहीं अब उनकी कार्यक्षमता बढ़कर लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ए.के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में और भी तेजी से आगे बढ़ेगा तथा देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा।

सम्पर्क सूत्र- प्रवीण मालवीय

जून माह में उत्तर प्रदेश के प्रमुख कर एवं करेत्तर राजस्व में 1,568 करोड़ रूपये की उल्लेखनीय वृद्धि

● वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम तिमाही में कर राजस्व के लक्ष्य का73.4 प्रतिशत हासिल- सुरेश कुमार खन्ना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था, पारदर्शी कर प्रशासन तथा प्रभावी राजस्व प्रबंधन के परिणामस्वरूप राज्य के प्रमुख कर एवं करेत्तर राजस्व मदों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रमुख कर राजस्व वाली मदों के अंतर्गत 60,825.60 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 73.4 प्रतिशत है। राज्य कर मद में 50,499.71 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष 31,928.64 करोड़ रूपये की प्राप्ति दर्ज की गई है। आबकारी मद में 16,500 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष 15,812.21 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित कर 95.8 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जबकि परिवहन विभाग ने 3,635.84 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3,667.98 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित कर 100.9 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रथम तिमाही के ये परिणाम प्रदेश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कर अनुपालन तथा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को दर्शाते हैं। खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून माह में प्रदेश के प्रमुख कर एवं करेत्तर राजस्व मदों से 19,551 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष जून, 2025 में यह प्राप्ति 17,983 करोड़ रूपये थी।

इस प्रकार प्रदेश ने गत वर्ष के जून माह की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के जून में 1,568 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत जून, 2026 में 7,279 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो जून, 2025 के 6,646 करोड़ रूपये के सापेक्ष 633 करोड़ रूपये अधिक है। इसी प्रकार वैट से जून, 2026 में 3,197 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 146 करोड़ रूपये अधिक है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार तथा कर अनुपालन में सुधार का परिणाम है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने जून, 2026 में 5,174 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष जून, 2025 की तुलना में 716 करोड़ रूपये अधिक है। वहीं परिवहन विभाग से 1,123 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 293 करोड़ रूपये की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत 428 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 96 करोड़ रूपये अधिक है। स्टाम्प एवं निबंधन मद में जून, 2026 के दौरान 2,350 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 316 करोड़ रूपये कम है। सुरेश कुमार खन्ना ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग राजस्व संग्रह की गति बनाए रखने, कर प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने तथा प्रदेश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

सम्पर्क सूत्र- जयेन्द्र सिंह

अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 18.49 करोड़ रुपये की द्वितीय किश्त जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से संचालित अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चार विकास परियोजनाओं के लिए 18.49 करोड़ रुपये (अट्ठारह करोड़ उनचास लाख चालीस हजार मात्र रुपये) की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के मरम्मत एवं नए निर्माण कार्य के लिए 735.73 लाख रुपये, आरसीसी कवर नालों, रिटेनिंग वॉल एवं कलवर्ट निर्माण के लिए 472.40 करोड़ रुपये, पार्क विकास एवं उद्यानीकरण के लिए 342.68 लाख रुपये तथा विद्युत लाइन अपग्रेडेशन, पथ प्रकाश, स्ट्रीट लाइट एवं हाईमास्ट स्थापना के लिए 298.59 लाख

रुपये अनुमन्य किए गये हैं। इन चारों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 33.59 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1509.81 लाख रुपये पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सम्पर्क सूत्र-सरिता वर्मा

16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में मंत्री ओ.पी. राजभर ने पंचायतों के हितों की उठाई आवाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- 16वें वित्त आयोग के अनुदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओ.पी. राजभर ने स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से वित्त आयोग की शर्तों और दिशा-निर्देशों को अधिक व्यावहारिक बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके समग्र विकास के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट की पात्रता शर्तों में व्यावहारिक संशोधन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए 'पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना' संचालित कर रही है, जिसके तहत पंचायतों को उनकी स्वयं की आय का पांच गुना तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित न्यूनतम आय की शर्त उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी और छोटी पंचायतों वाले राज्य के लिए व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने इसे शहरी निकायों की तरह सरल और समान बनाए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने टाइड एवं अनटाइड मद की गाइडलाइन शीघ्र जारी करने की आवश्यकता

बताते हुए कहा कि इनके अभाव में पेयजल, विकास कार्यों तथा पंचायत सहायकों एवं सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकर्स के मानदेय भुगतान में कठिनाई आ रही है। उन्होंने पूर्व वित्त आयोगों की भांति 10 प्रतिशत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद को पुनः बहाल करने की भी मांग की। राजभर ने यह भी कहा कि कुछ पंचायतों में लंबित मामलों के कारण पूरे प्रदेश की पंचायतों का अनुदान रोकना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल संबंधित पंचायतों पर कार्रवाई हो, जबकि शेष पंचायतों को समय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि केंद्र सरकार इन व्यावहारिक सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को नई गति मिलेगी।

धर्मार्थ कार्य योजना के अन्तर्गत 04 चालू कार्यो हेतु रू0 13 करोड़ 30 लाख की धनराशि की गयी अवमुक्त

लखनऊ: उ0प्र0 सरकार द्वारा धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत बस्ती मण्डल के विभिन्न जनपदों के मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत 04 चालू हेतु रू0 13 करोड़ 30 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

सम्पर्क सूत्र-अभिषेक सिंह

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के शिव विहार में पानी की समस्या से मिलेगी राहत, नई पेयजल लाइन बिछाने का काम शुरू

पूर्वी दिल्ली। मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल संकट की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थानीय विधायक व दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। क्षेत्र में लंबे समय से दूषित और गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोग लगातार विधायक कार्यालय और संबंधित विभाग के समक्ष समस्या उठा रहे थे। इस अवसर पर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि शिव विहार के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। नई पाइपलाइन बिछने से गंदे पानी की समस्या समाप्त होगी और हजारों परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। दिल्ली सरकार प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है और विकास कार्य आगे भी इसी गति से जारी रहेंगे।

सागरपुर में सुंदरकांड पाठ के दौरान बवाल, दिल्ली पुलिस पर किया था पथराव

पश्चिमी दिल्ली। सागरपुर में मंगलवार शाम सुंदरकांड पाठ के दौरान हुए बवाल और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण कर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हिंसा में शामिल सभी लोगों की भूमिका तय कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण-पश्चिमी जिला के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 30 जून को पूर्वी सागरपुर की गली नंबर-8 स्थित डीडीए पार्क में हुई मारपीट के संबंध में सागरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, धारा 126(2) किसी व्यक्ति की आवाजाही में अवैध रूप से बाधा डालने और धारा 3(5) समान उद्देश्य से मिलकर अपराध करने वाले सभी आरोपितों की समान जवाबदेही तय करने से संबंधित है। तत्काल क्षेत्र की स्थिति सामान्य बनी हुई है। बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तानी झंडा लहराने और आरोपितों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मंगलवार शाम पूर्वी सागरपुर की गली नंबर-8 स्थित डीडीए पार्क में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था। कार्यक्रम शुरू होने के दौरान ही पास की झुग्गी बस्ती के कुछ लोग वहां पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में तनाव में बदल गई। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से सुंदरकांड में शामिल लोगों पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने जब स्थिति को संभालने का प्रयास किया तो उस पर भी पथराव किया गया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, जिन्हें पुलिस जांच का महत्वपूर्ण आधार मान रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि प्रसारित वीडियो की फ्रेम-दर-फ्रेम जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी और फोरेंसिक सहायता भी ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह वारदात सुनियोजित तो नहीं थी और इसके पीछे कानून व्यवस्था बिगाड़ने और धार्मिक उन्माद फैलानी की कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी।

एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों का खेल उजागर

- तारीख बदलकर बाजार में बेच रहे थे सामान, कंपनी मालिक समेत सात गिरफ्तार

20 लाख रुपये से अधिक के एक्सपायर्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ, नकली लेबल और मशीनें बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने एक्सपायर्ड खाद्य एवं पेय पदार्थों की निर्माण और समाप्ति तिथि बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने कंपनी मालिक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद, नकली लेबल, बारकोड, एमआरपी स्टिकर, न्यूट्रिशन लेबल, प्रिंटिंग एवं सीलिंग मशीनें तथा एक्सपायरी डेट बदलने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं।पुलिस के मुताबिक आरोपी एक्सपायर्ड या एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके नामी कंपनियों के खाद्य एवं पेय पदार्थ कम कीमत पर खरीदते थे। इसके बाद केमिकल की मदद से उत्पादों पर अंकित निर्माण और समाप्ति तिथि मिटाकर विशेष मशीनों से नई तारीख छापी जाती थी। फिर नकली न्यूट्रिशन लेबल, बारकोड, बैच नंबर और एमआरपी स्टिकर लगाकर उत्पादों को नए पैकेट की तरह तैयार किया जाता था। बाद में इन्हें देशभर के बाजारों, खुदरा दुकानों, मॉल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नए उत्पाद के रूप में बेच दिया जाता था। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब पुलिस को ओखला फेज-2 स्थित एक कंपनी में बाल श्रमिकों से काम कराए जाने की सूचना मिली। इसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने उप-मंडल दंडाधिकारी बदरपुर मिशन मुक्ति फाउंडेशन और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की। जांच में बाल श्रमिक तो नहीं मिले, लेकिन फैक्टरी के भीतर एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी डेट बदलने का बड़ा खेल सामने आ गया। छापेमारी के दौरान थम्स अप, फैंटा, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मैगी नूडल्स, घी, पेपर बोट जूस, दो लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक कैन समेत बड़ी मात्रा में पैकेज्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ बरामद किए गए। इसके अलावा नकली लेबल, न्यूट्रिशन स्टिकर, बारकोड, बैच नंबर, एमआरपी टैग, प्रिंटिंग मशीन, सीलिंग मशीन और एक्सपायरी डेट बदलने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक्सपायर्ड और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके उत्पादों को सस्ते दामों में खरीदते थे। इसके बाद रसायनों की मदद से पुरानी निर्माण और समाप्ति तिथि मिटाकर नई तारीख छापी जाती थी। नकली लेबल और स्टिकर लगाकर उत्पादों को दोबारा पैक किया जाता था और बाजार में नए उत्पाद के रूप में सप्लाई कर दिया जाता था। पुलिस के अनुसार इस अवैध कारोबार से आरोपी भारी मुनाफा कमा रहे थे, जबकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था। इस मामले में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एफआईआर संख्या 358/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 275, 318(4), 336, 340 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

झपुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसकी सप्लाई चेन की जांच कर रही है।गिरफ्तार आरोपियों में 70 वर्षीय दर्शन सिंह सचदेवा, जो कंपनी के मालिक हैं, 38 वर्षीय नितेश भारद्वाज (प्रबंधक), 42 वर्षीय नरेंद्र कुमार (लेखाकार), 34 वर्षीय कपिल (ऑपरेटर), 45 वर्षीय लकी ओझा वेयरहाउस कीपर 33 वर्षीय प्रेम यादव (सुपरवाइजर) और 32 वर्षीय पवन कुमार यादव (सुपरवाइजर) शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर इस फर्जीवाड़े के नेटवर्क और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी चार साल में 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश , 30 हजार से अधिक चार्जिंग केंद्र बनेंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देना और आवश्यक आधारभूत ढांचे का विस्तार करना है।नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे नीति का एक प्रमुख लक्ष्य राजधानी में चार्जिंग सुविधाओं का व्यापक विस्तार करना भी है। इसके तहत पूरे दिल्ली में 30 हजार से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने में आसानी होगी और चार्जिंग नेटवर्क पहले की तुलना में अधिक सुलभ एवं मजबूत बनेगा।इसके साथ ही, नीति में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से कबाड़ घोषित कर हटाने की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी की परिवहन व्यवस्था अधिक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बन सकेगी। दिल्ली सरकार के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी प्रबंधन और इससे जुड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और साथ-साथ हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को शून्य उत्सर्जन वाली परिवहन राजधानी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था, आधुनिक चार्जिंग सुविधाओं और पर्यावरण हितैषी नीतियों के माध्यम से प्रदूषण कम करने तथा लोगों को बेहतर सार्वजनिक और निजी परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल का नया दांव: पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी, जनता के फीडबैक को करेंगे शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की तैयारी की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पूरा देश उसके लिए प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जबरदस्ती श्व20 पेट्रोल लोगों पर थोप रही है, जिससे वाहनों में इंजन बंद पड़ रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी काफी घट गया है। केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि वह इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं और सुझाव उन्हें डायरेक्ट मैसेज (DM) या कमेंट के जरिए भेजें, ताकि चिट्ठी में इन मुद्दों को शामिल किया जा सके। यह पोस्ट E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसमें विपक्षी नेता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं।

बारिश के मौसम को देखते हुए घग्गर नदी में पानी के आसान बहाव के लिए 5 ज़रूरी जगहों पर डी-सिल्टिंग की मंज़ूरी

- डी-सिल्टिंग का काम तुरंत पूरा करने के निर्देश: डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मानसा– बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने और पहले से किए गए इंतज़ामों को मज़बूत करने के लिए, ज़िला प्रशासन लगातार अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर रहा है और इंतज़ामों का रिव्यू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक मीटिंग के दौरान, घग्गर नदी में बारिश के पानी के आसान बहाव को पक्का करने के लिए 5 ज़रूरी जगहों पर मिट्टी और सिल्ट हटाने और सफ़ाई (डी-सिल्टिंग) के काम को मंज़ूरी दी गई है। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन सभी तय जगहों पर डी-सिल्टिंग का काम तुरंत पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि बारिश के दिनों में पानी के नैचुरल बहाव में कोई रुकावट न आए और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान से बचा जा सके। पंजाब सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, घग्गर नदी में पानी की निकासी को आसान बनाने के लिए, घग्गर के पास गांव सरदुलेवाला, गांव ढिंगाना, भगवानपुर हिंगना और अहलूपुर के आस-पास के इलाकों, गांव भलनवाड़ा, गांव फूस मंडी और मीरपुर खुर्द के आस-पास के इलाकों और घग्गर नदी सरदूलगढ़ के पास स्टील फुट ब्रिज पर डी-सिल्टिंग की जाएगी। मीटिंग के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने खास तौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सरदूलगढ़ हरजिंदर सिंह जस्सल को घग्गर नदी और इलाके के दूसरे बरसाती नालों में पानी के लेवल पर लगातार नज़र रखने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने दोहराया कि जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इस मीटिंग में एसपी प्रदीप संधू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेनेज परमिंदर सिंह, असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉ. बलजीत कौर और दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

'ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026' के तहत लुधियाना में छात्रों के साथ किया सीधा संवाद

- 12वीं कक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और मनीष सिसोदिया ने किया सम्मानित

पंजाब के स्कूलों में अगले महीने से शुरू होगा ए.आई. पाठ्यक्रम: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना– 'ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026' अभियान के तहत आज गुरु नानक देव भवन, लुधियाना में एक विशाल और प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और शिक्षा प्रणाली में हो रहे आधुनिक बदलावों व सुधारों पर विचार-विमर्श करना था। इस अवसर पर 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। छात्रों की हौसलाअफजाई करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि ये बच्चे न केवल अपने परिवारों का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि पंजाब और पूरे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये मेधावी छात्र आने वाले समय में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील और अन्य उच्च पदों पर आसीन होकर देश की महान सेवा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि यह पहली बार है जब शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने खुद छात्रों के बीच बैठकर परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और पढ़ाई के तौर-तरीकों पर खुली चर्चा की है। बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे बेहद व्यावहारिक और समय के अनुकूल हैं, जिन्हें भविष्य की नीतियां बनाते समय लागू किया जाएगा। स. हरजोत सिंह बैंस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में ए.आई. एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। पंजाब सरकार पिछले एक साल से इस योजना पर लगातार काम कर रही है और अगले महीने से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 'ए.आई. पाठ्यक्रम' लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने गर्व के साथ साझा किया कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करते हुए केरल को पीछे छोड़ दिया है और भारत के शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति का रास्ता वहां की मजबूत शिक्षा प्रणाली से होकर गुजरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। ए.आई. तकनीक पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं कुछ पारंपरिक नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमारे छात्रों को नई तकनीक के अनुरूप तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने, नकल की प्रवृत्ति को रोकने और शिक्षण के नए वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर भी बल दिया। इस अवसर पर शिक्षा सचिव सोनाली गिरी ने भी शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने नशे, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली की कमियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने, अपनी मातृभूमि, समृद्ध संस्कृति और पंजाब के पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आने का संकल्प भी दिलाया। यह समारोह शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को एक नए मुकाम पर ले जाने और छात्रों की आवाज को नीति-निर्माण में महत्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस प्रभावशाली समारोह के दौरान क्षेत्रीय विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल, स्कूल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सकतर सिंह बल, अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) डॉ. नरिंदर धालीवाल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (लुधियाना पूर्वी) जसलीन कौर भुल्लर, जिला शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान और मंच संचालक के रूप में नेशनल अवॉर्डी मास्टर करमजीत सिंह ग्रेवाल के अलावा राज्य भर से बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक उपस्थित थे।

नारी शक्ति का जागरण: आधुनिक भारत की अमिट आभा: डॉ ज्ञानवती दीक्षित

- 'इतना सच बोल कि होंठों का तबस्सुम न बुझे, रौशनी खत्म न कर, आगे अंधेरा होगा' – निदा फ़ाज़ली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारत में नारी सदा से पूजनीय रही है। प्राचीन ग्रंथों में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः' का मंत्र गूंजता है। नारी सृष्टि का आधार है – लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का स्वरूप। लेकिन विडंबना यह है कि विदेशी आक्रमणों, सामाजिक बंधनों और पुरुष-प्रधान व्यवस्था ने इस शक्ति को सीमित कर दिया। आज आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का अपरिहार्य स्तंभ बन चुका है।

सशक्तिकरण का अर्थ– सशक्तिकरण वह क्षमता है जिसमें महिला स्वयं अपने जीवन के हर निर्णय की निर्माता बन सके। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक मुक्ति का समग्र रूप है। जब नारी बंधनों से मुक्त होकर फैसले लेती है, तब परिवार और समाज दोनों समृद्ध होते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ– दुर्भाग्य से आज भी दहेज, बाल-विवाह, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसी कुरीतियाँ मौजूद हैं। शिक्षा में लैंगिक असमानता स्पष्ट है – पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 81% है जबकि महिलाओं की करीब 60-65%। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ महिलाएँ मुख्यतः कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। कार्यस्थल पर भी भेदभाव जारी है। समान योग्यता के बावजूद महिलाओं को पुरुषों से 20% कम वेतन मिलता है। शहरी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर उद्योग में केवल 30% महिलाएँ हैं, जबकि ग्रामीण भारत में 90% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में संघर्ष करती हैं। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हरियाणा और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। पुरानी रूढ़िवादी सोच महिलाओं को घर के अंदर कैद रखती है और उन्हें आत्मविश्वास से वंचित करती है।

प्रगति की किरणें– फिर भी आशा की किरणें दिख रही हैं। सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मिशन शक्ति और मातृ दिवस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और एनजीओ के प्रयासों से जागरूकता बढ़ी है। आधुनिक भारत में कई महिलाएँ राजनीतिक, प्रशासनिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में उच्च पदों पर विराजमान हैं। शहरी महिलाएँ शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ रही हैं।

आवश्यकता और संकल्प– देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। शिक्षा, समान वेतन, सुरक्षा और अवसरों की समानता प्रदान करनी होगी। समाज को रूढ़ियों को तोड़ना होगा। महिलाएँ स्वयं भी आत्मनिर्भरता की राह चुनें।

उठो नारी, युग निर्माण तेरा है– नारी ममता की मूर्ति है, सृजन की शक्ति है। वह पथ-दुलारी है, जो कठिनाइयों को पार करती हुई आगे बढ़ती है। जब हर घर में नारी का सम्मान होगा, तभी देवी-पूजन सार्थक होगा। आइए मिलकर संकल्प लें – लैंगिक समानता, शिक्षा और सुरक्षा के माध्यम से नारी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आधुनिक भारत की प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसकी आधी आबादी पूर्ण शक्ति से आगे बढ़ेगी। नारी शक्ति नहीं रुक सकती – वह तो राष्ट्र की धड़कन है।

शहर में भारी बारिश के बाद, म्युनिसिपल कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने फील्ड इंस्पेक्शन किया

अधिकारियों/कर्मचारियों को दिन-रात सतर्क रहने के निर्देश दिए

लुधियाना– बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को शहर में भारी बारिश के बाद, म्युनिसिपल कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने गुरुवार सुबह हालात का जायज़ा लेने के लिए फील्ड इंस्पेक्शन किया। भाई बाला चौक, सग्गू चौक, फिरोजपुर रोड समेत कई इलाकों का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान जोनल कमिश्नर जसदेव सेखों, हेल्थ ऑफिसर डॉ. विपल मल्होत्रा और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। अलंकार ने कहा कि भारी बारिश की वजह से शहर में कुछ जगहों पर पानी जमा हुआ देखा गया, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही ज़रूरी कदम उठा लिए थे, इसलिए यह कुछ ही देर में निकल गया। उन्होंने कहा कि हालात पर दिन-रात नज़र रखने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। सग्गू चौक के पास सड़क टूटने वाली जगह का भी इंस्पेक्शन किया गया और रिपेयर के काम में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए। म्युनिसिपल कमिश्नर अलंकार ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस की लीडरशिप में 'मिशन क्लीन पंजाब' के तहत काम करते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर शिकायतों को हल करने के लिए रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर अलंकार ने आगे कहा कि मॉनसून की तैयारियों के बारे में अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं और इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दक्षिण जिला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

- 8.598 किलोग्राम चरस के साथ तीन नेपाली नागरिक गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिला स्पेशल स्टाफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8.598 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता की चरस बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में थाना कोटला मुबारकपुर में एफआईआर संख्या 129/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 और 29 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस के अनुसार, स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कोटला मुबारकपुर इलाके में रहने वाले तीन नेपाली नागरिक दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर चरस की सप्लाई कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने 29 जून को आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 8.598 किलोग्राम चरस बरामद की गई और तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ज्योति पुन मगर इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर है। वह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर के माध्यम से नेपाल से चरस मंगवाता था। इसके बाद आरोपी भरत थापा और गोविंद बुढ़ा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इसकी सप्लाई करते थे।पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान लेते थे। हर डिलीवरी के बाद वे चैट और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते थे, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके।

डिलीवरी के लिए ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल भुगतान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय भरत थापा, 32 वर्षीय गोविंद बुढ़ा और 50 वर्षीय ज्योति पुन मगर के रूप में हुई है। तीनों मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं और वर्तमान में कोटला मुबारकपुर के नानक चंद बस्ती क्षेत्र में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, तीनों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। बरामद चरस में 5.566 किलोग्राम ज्योति पुन मगर, 1.552 किलोग्राम भरत थापा और 1.480 किलोग्राम गोविंद बुढ़ा के कब्जे से बरामद की गई।इस पूरी कार्रवाई को इंस्पेक्टर अनुज कुमार के नेतृत्व में तथा एसीपी ऑपरेशंस रितु राज की निगरानी में एसआई नवीन, एसआई अमित, एएसआई पदम, हेड कांस्टेबल राकेश प्रवीण, मनीष, कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल खोइचुंग बिल की टीम ने अंजाम दिया।दक्षिण जिला पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से भारत-नेपाल सीमा के रास्ते संचालित अंतरराष्ट्रीय चरस तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब नेपाल स्थित मुख्य सप्लायर, डिजिटल लेन-देन और पूरे तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने में जुटी है। मामले की जांच जारी है।

30 सितंबर तक कई सिविक सर्विस की फीस माफ: डिप्टी कमिश्नर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

होशियारपुर– डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि पंजाब सरकार ने वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कैंपेन को लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाने के मकसद से 30 सितंबर, 2026 तक कई ज़रूरी सिविक सर्विस पर सरकारी फीस और सुविधा चार्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के दौरान, बड़ी संख्या में लोगों को संबंधित अधिकारियों के पास कई तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने तीन महीने के समय के लिए कई ज़रूरी सर्विस को फ्री में उपलब्ध कराने का फैसला किया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन सर्विस पर यह छूट लागू होगी, उनमें जाति सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी सर्विस और 10वीं और 12वीं क्लास के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने जैसी ज़रूरी सर्विस शामिल हैं। नागरिक 30 सितंबर, 2026 तक इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह सुविधा सर्विस सेंटर, घर के पास उपलब्ध नागरिक सेवाओं और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को समय पर और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने दस्तावेज़ प्राप्त करने में सुविधा होगी। आशिका जैन ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन अभियान के तहत, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मांग में वृद्धि हुई है। ऐसे में पंजाब सरकार का यह फैसला नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जर्जर मकान का छज्जा गिरा, महिला की मौत

देवरिया। जनपद के गौरीबाजार कस्बे के वार्ड नंबर दो स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा बगल के टीन शेड पर गिरने से उसमें रह रही 45 वर्षीय फूला देवी की मौत हो गई, जबकि उनके दो बच्चे घायल हो गए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर सतेन्द्र कुमार राय ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।